भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 578

उत्तर देने की तारीख 24 जुलाई, 2023 (सोमवार)

2 श्रावण, 1945 (शक)

प्रश्न

पीएम-डिवाइन योजना

578. श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में पीएम-डिवाइन योजनाओं के अंतर्गत इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का परियोजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

*****

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) की घोषणा केन्द्रीय बजट 2022-23 में 100% केन्द्रीय वित्तपोषण के साथ एक नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी, जिसमें सात परियोजनाओं की प्रारंभिक सूची के साथ 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया गया था। 12 अक्टूबर, 2022 को पीएम-डिवाइन स्कीम के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम में वर्ष 2022-23 से 2025-26 (15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्षों) तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

पीएम-डिवाइन स्कीम के उद्देश्य हैं: (i) पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप अवसंरचना को समेकित रूप से वित्त पोषित करना; (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को सहायता देना; (iii) युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका कार्यकलापों को सक्षम बनाना; और (iv) विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कमियों को दूर करना। स्कीम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बजट 2022-23 में घोषित सात परियोजनाओं सहित 1,503.44 करोड़ रुपये की ग्यारह परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2022-23 में मंजूरी के लिए चुना गया है और 121.10 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य-वार तथा परियोजना-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) पीएम-डिवाइन स्कीम की परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए निर्धारित समय-सीमा वर्ष 2023-24 और पूर्णता के लिए वर्ष 2025-26 है।

अनुबंध-I

<u>वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य-वार, परियोजना-वार सूची</u>

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना स्थल/राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी / विभाग	अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में)
1	पूर्वोत्तर भारत में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमेटोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना, गुवाहाटी	गुवाहाटी - बहु-राज्य	डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, परमाणु ऊर्जा विभाग	129
2	नैक्टर आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) - मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए केले के स्यूडो स्टेम का उपयोग	7 राज्यों में 12 स्थान: अरुणाचल प्रदेश (1), असम (4), मणिपुर (1), मेघालय (1), मिजोरम (1), नागालैंड (2), त्रिपुरा (2)	उत्तर-पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान केन्द्र (नैक्टर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	67
3	पूर्वोत्तर भारत में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देना (बहु-राज्य)	मेघालय, असम और त्रिपुरा में डेमो लैब्स	उत्तर-पूर्व प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं अनुसंधान केन्द्र (नैक्टर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	45
4	पश्चिम सिक्किम में पेलिंग से सांगा-चोइलिंग तक यात्री रोपवे प्रणाली के लिए गैप फंडिंग - 108.39 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 63.39 करोड़ रुपये (58%) की लागत से।	पश्चिम सिक्किम-सिक्किम	पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार	64
5	दक्षिण सिक्किम में धापर से भालेडुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल यात्री रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग - 209.57 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 57.82 करोड़ रुपये (28%) की लागत से।	दक्षिण सिक्किम-सिक्किम	पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग, सिक्किम सरकार	58
6	पश्चिमी तरफ आइजोल बाईपास रोड का निर्माण	मिजोरम में सिंहमुई में एनएच -108 से आइजोल-लुंगलेई रोड तक 45 किमी	लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार	500
7	मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए पायलट	तुइरियल एयरफील्ड से नॉर्थ चाल्टलांग; और लेंगपुई से सैफल, मिजोरम	लोक निर्माण विभाग, मिजोरम सरकार	100

	परियोजना - (i) 33.58 करोड़ रुपये की लागत से तुइरियल एयरफील्ड से उत्तरी चाल्टलांग (18 किमी); (ii) 66.42 करोड़ रुपये की लागत से लेंगपुई से सैफल बांस रोपण (41 किमी)			
8	न्यू शिलांग टाउनशिप में नई चार-लेन सड़क का निर्माण और मौजूदा दो-लेन सड़क को साइकिल ट्रैक, यूटिलिटी डक्ट्स, फुटपाथों आदि के साथ चार-लेन में परिवर्तित करना	न्यू शिलांग, मेघालय	शहरी कार्य निदेशालय, मेघालय सरकार	146.79
9	कामरूप जिले में 20 स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलना	कामरूप जिला, असम	लोक निर्माण विभाग, असम सरकार	132.86
10	त्रिपुरा में दूरस्थ बस्तियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना	त्रिपुरा राज्य में दूरदराज के 274 गांव	टीआरईडीए, विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार	80.79
11	पूर्वी नागालैंड के विशेष विकास से संबंधित आजीविका परियोजनाएं - (22 परियोजनाएं)	नागालैंड के 4 जिले	अल्पविकसित क्षेत्र विभाग (डूडा), नागालैंड सरकार	180

*****